प्रसार भारती
भारतीय प्रसारण निगम
आकाशवाणी केन्द्र शिमला
29.11.2024 / प्रादेशिक समाचार / 18.00 बजे

मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने केन्द्रीय वाणिज्य व उद्योग मंत्री पीयूष गोयल से हिमाचल प्रदेश के लिए विशेष औद्योगिक पैकेज प्रदान करने का आग्रह किया है। मुख्यमंत्री ने कल नई दिल्ली में केन्द्रीय मंत्री से भेंट के दौरान कहा कि हिमाचल को जम्मू–कश्मीर और पूर्वोत्तर राज्यों की तर्ज़ पर विशेष औद्योगिक पैकेज प्रदान किया जाए। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पहाड़ी क्षेत्रों के लिए पहले की तरह परिवहन सब्सिडी योजना को फिर से शुरू करने का आग्रह भी किया। उन्होंने कहा कि इससे औद्योगिक उत्पाद और निर्यात को बढ़ावा देने में काफी मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री ने निर्यात प्रोत्साहन के लिए औद्योगिक अधोसंरचना विकास परियोजनाओं, गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशालाओं और प्रमाणन प्रयोगशालाओं के लिए उदार वित्तीय सहायता देने की मांग भी की। इसके अलावा उन्होंने औद्योगिक विकास योजना के तहत पूंजीगत सब्सिडी की लंबित राशि जारी करने का भी केन्द्रीय मंत्री से अनुरोध किया। केन्द्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने राज्य सरकार की सभी मांगों और मुद्दों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने और प्रदेश को हरसंभव सहायता प्रदान करने का आश्वासन दिया।

सिकंदर कुमार

केन्द्रीय गृह व सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि केन्द्र सरकार ने तीन राष्ट्रीय स्तर की बहुराज्यीय सहकारी समितियों की स्थापना की, जिसमें राष्ट्रीय सहकारी, निर्यात लिमिटेड, राष्ट्रीय सहकारी ऑग्रेनिक्स लिमिटेड और भारतीय बीज सहकारी समिति शामिल हैं। राज्यसभा सांसद सिकंदर कुमार द्वारा संसद में हिमाचल प्रदेश में जैविक कृषि, प्रमाणित बीज और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय स्तर की नई बहुराज्यीय समितियां स्थापित करने के संबंध में पूछे गए सवाल के जवाब में उन्होंने ये बात कही। अमित शाह ने बताया कि इन समितियों को बहुराज्यीय सहकारी सोसाइटी अधिनियम–2002 के अधीन पंजीकृत किया गया है। उन्होंने कहा कि सभी सहकारी समितियां जो प्रत्येक समिति के लिए निर्देशित गतिविधियों में रूचि रखते हैं, जिसमें हिमाचल प्रदेश सहकारी अधिनियम के तहत पंजीकृत समितियां भी शामिल हैं। सांसद सिकंदर कुमार के एक अन्य सवाल के जवाब में अमित शाह ने कहा कि केन्द्र सरकार को सहकारी शिक्षा, प्रशिक्षण, अनुसंधान विकास और प्रशिक्षित कार्य बल की गुणवत्ता के लिए राष्ट्रीय स्तर के सहकारी विश्वविद्यालय के स्थापना के लिए प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं।

यादविंदर गोमा

आयुष, युवा सेवाएं व खेल मंत्री यादविंदर गोमा ने कहा है कि वर्तमान प्रदेश सरकार ने खिलाड़ियों की प्रोत्साहन राशि में अभूतपूर्व बढ़ौतरी कर खिलाड़ियों का सम्मान किया है। कांगड़ा ज़िला

के पंचरूखी में 21वीं अखिल भारतीय डॉक्टर यशवंत सिंह परमार मेमोरियल वॉलीबॉल प्रतियोगिता का शुभारंभ करने के बाद लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बात कही। तीन दिवसीय स प्रतियोगिता में देश की 8 टीमें भाग ले रही हैं। इस अवसर पर गोमा ने कहा कि प्रदेश में 20 स्टेडियमों का निर्माण कार्य प्रगति पर है और इस वित्त वर्ष में उच्च स्तरीय खेल अधोसंरचना के लिए 28 करोड़ रूपये से अधिक की राशि खर्च की जा रही है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री युवा खेल प्रोत्साहन योजना के तहत प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में एक खेल मैदान बनाने के लिए 15 लाख रूपये की राशि उपलब्ध करवाई जा रही है। यादविंदर गोमा ने कहा कि खेलों को बढ़ावा देने के लिए सिरमौर के मजरा में हॉकी एस्ट्रोटर्फ मैदान का निर्माण किया गया है।

रणधीर शर्मा

भाजपा विधायक व प्रदेश भाजपा मीडिया प्रभारी रणधीर शर्मा ने कहा है कि सुक्खू सरकार अपने कृत्यों से हीन भावना में ग्रस्त है और विपक्ष के सवालों के जवाब देने की सरकार में हिम्मत नहीं है। शिमला में आज पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि विधानसभा सत्र भले ही छोटा रखा गया है लेकिन विपक्ष चार दिन में भी मजबूती से जनता के मुद्दों को सदन में उठाएगा। प्रदेश सरकार के दो साल के कार्यकाल के जश्न और विधानसभा सत्र को लेकर सवाल उठाते हुए रणधीर शर्मा ने कहा कि विधानसभा अध्यक्ष का पद संवैधानिक है और उसका विपक्ष भी सम्मान करता है लेकिन विधानसभा अध्यक्ष के बयान ठीक नहीं है। उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष को अपने पद की गरिमा बनाए रखने की सलाह भी दी। रणधीर शर्मा ने कहा कि भाजपा सरकार के जनविरोधी निर्णयों को लेकर जनता के बीच में जाएगी और सरकार की कार गुजारियों का पर्दाफाश किया जाएगा।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग जल्द ही स्नातक छात्रों के लिए डिग्री पाठ्यक्रमों की अवधि कम करने या उसे बढ़ाने का विकल्प प्रदान करेगा। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने त्वरित और विस्तारित डिग्री कार्यक्रम के लिए मानक प्रचालन प्रक्रियाओं को मंजूरी दे दी है। आयोग के अध्यक्ष जगदीश कुमार ने मीडिया को बताया कि त्वरित डिग्री कार्यक्रम से छात्रों को प्रति सेमेस्टर अतिरिक्त क्रेडिट अर्जित करके कम समय में तीन साल या चार साल की डिग्री हासिल कर सकेंगे।